पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की विविध अपील संख्या. 528

==========

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) पटना, 5वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

.....अपीलकर्तागण

बनाम

श्री राजेंद्र सेठिया, पुत्र स्वर्गीय शोभमलजी सेठिया, निवास-101, पलाश, डीएम वाटिका, खमरडीह, कचना रोड, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

<u>हेडनोट</u>

सीमा शुल्क अधिनियम्, 1962 - धारा 129 A(2) - दो किलोग्राम सोना हावड़ा से मुम्बई जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के शरीर से प्रतिबंधित पदार्थ के रुप में जब्त किया गया तथा जुर्माना लगाया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने मूल प्राधिकरण के आदेश को उलट दिया। न्यायाधिकरण ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि की। - देश के बाहर निर्मित सोने का मालिक कोई भी हो, यदि इसे उसी रुप में जब्त किया जाता है, तो उक्त सोने को जारी करने का दावा करने वाले मालिक को प्राधिकरण के समक्ष स्पष्ट रुप से यह स्थापित करना चाहिये कि इसे सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत्त भारत में लाया गया था। - धारा 123 द्वारा स्त्रोत को स्थापित करने की जिम्मेवारी मालिक पर है।

हम अपीलय प्राधिकरणों के आदेशों को दरकिनार करते हैं तथा मूल प्राधिकरण के आदेशों को बहाल करते हैं।

हम 5000/- रुपये की गणना की गई लागत के साथ अपील की अनुमति देते हैं।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की विविध अपील संख्या. 528

==========

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) पटना, 5वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

.....अपीलकर्तागण

बनाम

श्री राजेंद्र सेठिया, पुत्र स्वर्गीय शोभमलजी सेठिया, निवास-101, पलाश, डीएम वाटिका, खमरडीह, कचना रोड, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए:- डॉ. के. एन. सिंह एएसजी

श्री अंशुमन सिंह, वरिष्ठ एससी, सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स.

श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

श्री देवनाथ शंकर सिंह अधिवक्ता,

प्रतिवादी/ओं के अधिवक्ताः- श्री साकेत गुप्ता, अधिवक्ता

श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री हरीश कुमार

सी.ए.भी. निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तिथी:- 21-03-2024

स्विस चिह्नों के साथ दो किलोग्राम सोना, जो निस्संदेह विदेश से इसके स्रोत का संकेत देता है, परिवहन की पूर्व सूचना पर जब्त किया गया था, जिसके आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षिप्तता के लिए 'अधिनियम') के तहत कार्यवाही की गई थी, जो मूल आदेश (अनुलग्नक-बी) में रूपांतरित हुई, अधिनियम के तहत ज़ब्त और जुर्माना लगाया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने मूल प्राधिकरण के आदेश को उलट दिया। अधिनियम की धारा 129-ए (2) के तहत, आयुक्तों की समिति ने उचित अधिकारी को अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का निर्देश दिया; जिसमें न्यायाधिकरण ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि की। विवादित अपील अधिनियम की धारा 130 के तहत दायर की गई है, जिसमें कानून का निम्नलिखित सवाल उठाया गया हैः

> *"क्या अपीलीय प्राधिकरण ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने निष्कर्षों में पूरी तरह से गलती की है और कई भौतिक तथ्यों के साथ-साथ उद्धृत निर्णयों की अनदेखी करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा है?"*

2. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के.एन. सिंह ने तर्क दिया कि हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के शरीर

से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था; हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस, में जब उक्त व्यक्ति को रोका गया और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तलाशी ली गई। प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पर, जिसके पास कोई सहायक दस्तावेज नहीं थे, उस व्यक्ति को पटना लाया गया जहां उसने अधिनियम की धारा 108 के तहत एक शपथ बयान दिया था, जिसका एक साक्ष्य मूल्य है। बयान को बाद में वापस ले लिया गया था, जब व्यक्ति को जमानत दी गई थी; जो ऐसे मामलों में सामान्य है और यह बयान के साक्ष्य मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, अगर बयान, कम से कम कुछ पहलुओं में, अन्य भौतिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किए जाते है। रोके गए व्यक्ति द्वारा दी गई कहानी को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित किया गया था, और मालिक के साथ-साथ उन व्यक्तियों को भी तलब किया गया था जिन पर मालिक को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया था। धारा 108 के तहत अधिकारी द्वारा जांचे गए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी थे, इस प्रकार, दिए गए स्पष्टीकरण को जोखिम में डालते थे।

3. सोने की छड़ पर स्विस निशान स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित पदार्थ के स्रोत को स्थापित करते हैं, जो देश के बाहर से था। यह उस व्यक्ति के लिए था जिससे प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था और कथित मालिक को यह स्थापित करना था कि प्रतिबंधित पदार्थ देश में कैसे आया। देश के भीतर एक लेन-देन का संकेत देने वाला केवल चालान, आयातित माल के रूप में माल को जब्ती से मुक्त नहीं करेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहे और जांच में बरामद भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की, जिससे आदेश पूरी तरह से विकृत हो गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, गलत विचार पर और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर, उचित अधिकारी से एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा; वह अधिकारी जिसने मूल आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने केवल प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आधारों का उल्लेख किया और उन्हें निकाला, इस प्रकार, इसे दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग के बिना अपनाया।

4. कथित मालिक द्वारा प्रस्तुत चालान, हालांकि ज़ब्त किए जाने से पहले के हैं, यह माना जाता है कि उस समय कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था। कथित मालिक की शपथ पर जांच के बाद ही जब्ती और आंशिक भुगतान के बाद ही प्रतिफल का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत स्पष्टीकरण और प्रकट किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि चालान एक मनगढ़ंत दस्तावेज था। कथित विक्रेता से खरीदार को सोने की बिक्री और परिवहन के लेन-देन को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। विक्रेता और खरीदार के बीच कोई पूर्व लेनदेन नहीं था, जो दिए गए ऋण को दोगुना संदिग्ध बनाता है। धारा 108 के तहत बयान के लिए पर्याप्त पुष्टि थी और दोनों अपीलीय अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। **रिलायंस को नरेश जे. सुखवानी बनाम भारत संघ पर रखा गया है। 1995 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 663, सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 1 एस. सी. सी. 508, के. आई. पावन्नी बनाम सहायक। समाहर्ता (मुख्यालय), केन्द्रीय आवकारी समाहर्ता कोच्चि, (1997) 3 एस. सी. सी. 721 पर भरोसा रखा गया है।**

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपीलीय अधिकारियों के आदेशों को बनाए रखने के लिए जोरदार तर्क दिया। पहले यह तर्क दिया जाता है कि अवरोधन उचित नहीं था और कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई थी, जो के अनुसार अनिवार्य था। टाटानगर एक अधिसूचित क्षेत्र नहीं था और विश्वास करने के कारणों की रिकॉर्डिंग, जो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है, भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। धारा 108 के तहत बयान धमकी और जबरदस्ती के तहत था और पहले अवसर पर ही वापस ले लिया गया था। बयान राजस्व खुफिया निदेशालय (डी. आर. आई.) की हिरासत में दिया गया था और बाद में जिस व्यक्ति को रोका गया था, उसे क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिन गवाहों ने धारा 108 के तहत बयान पर अपने हस्ताक्षर किए, उन्हें गवाह कहा जाता है जो अवरोधन के समय मौजूद थे। यह विश्वास करना

मुश्किल है कि वही स्वतंत्रता गवाह धारा 108 के तहत बयान को देखने के उद्देश्य से टाटानगर से पटना गए थे।

6. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब्त किया गया सोना विदेशी मूल का था। कार्यवाही इस धारणा पर थी कि सोने की छड़ें बांग्लादेश से देश में तस्करी करके लाई गई थीं; जो धारणा केवल धारा 108 के तहत बयान से उत्पन्न होती है। प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला यह था कि चालान माल के साथ थे और उन्हें अवरोधन पर प्रस्तुत किया गया था; जिसे अवरोधन अधिकारी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इन वस्तुओं को कारीगर निर्गम पर्ची द्वारा भी समर्थन दिया गया था। 'करीगर निर्गम पर्ची' एक 'शुभ करीगर' द्वारा आभूषणों के निर्माण के उद्देश्य से ले जाए जाने वाली सोने की छड़ें दर्शाती है। इन दस्तावेजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और पंचनाम में शामिल नहीं किया गया था। 24.07.2017 के बहुत शुरुआती घंटों में आधी रात के तुरंत बाद तलाशी ली गई, लेकिन गिरफ्तारी केवल 21:30 बजे हुईः30 घंटे; जिस समय तक, पकड़ा गया व्यक्ति डी. आर. आई. अधिकारियों की हिरासत में था।

7. चंदना इम्पेक्स (पी) लि० बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2011) 7 एस. सी. सी. 289 पर भरोसा रखा गया यह तर्क देने के लिए कि अपील से उत्पन्न होने वाले कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। **ए. ताजुद्दीन बनाम भारत संघ; (2015) 4 एससीसी 435** था यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, विशेष रूप से जब, तत्काल मामले में, गिरफ्तारी में देरी हुई थी और इसी तरह क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया था। अधिनियम की धारा 108 के तहत शपथ पत्रों के साक्ष्य मूल्य के बारे में राज्य के तर्क को दूर करने के लिए, राज्य के आयुक्त पर निर्भरता रखी गई थी। **सीमा शुल्क (आयात), मुंबई बनाम गणपति इसके मालिक श्री यशपाल शर्मा और अन्य के माध्यम से। (2023) 10 एससीसी**

484। विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ और अन्य। (2008) 16 एस. सी. सी. 537 धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान की पुष्टि की आवश्यकता के संबंध में आधारों को और मजबूत करने के लिए भी भरोसा किया गया था, यदि जबरदस्ती और धमकी के आरोप पर बाद में वापस ले लिया गया। इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा **ओम साई ट्रेडिंग कंपनी और अन्य बनाम भारत संध और अन्य 2019 ऑनलाईन पैट 2262** पर भी भरोसा किया गया था।

8. अपीलीय आदेशों के समर्थन में और मूल आदेश को चुनौती देने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए आधार प्रारंभ से ही शुरू होते हैं; अवरोधन के समय से ही। हम इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि हम अपीलीय अधिकारियों के आदेश में दर्ज तथ्यों पर निष्कर्षों से अपील नहीं कर रहे हैं और हम, धारा 130 के तहत, केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि **चंदना इम्पेक्स (पी) लिमिटेड** (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायाधिकरण अंतिम तथ्य खोजने वाला प्राधिकरण होने के नाते, यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वह उन आधारों की जांच करे जिनके आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य निष्कर्ष निकाले गए थे। हालाँकि, इस तरह का अवलोकन करते समय, यह भी राय दी गई थी कि उस मामले में न्यायाधिकरण का आदेश, जो अनिवार्य रूप से आयुक्त के आदेश को संदर्भित करता है, कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देता है, क्योंकि आयुक्त का विश्लेषण व्यापक था। यह भी देखा गया कि न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए कोई सवाल नहीं उठाया गया था, जैसा कि विकृत (एस. आई. सी.-पैरा-15) था।

9. वर्तमान मामले में, हमने विधि के प्रश्न को निकाला है। जो स्पष्ट रूप से अपीलीय अधिकारियों पर है कि उन्होंने भौतिक तथ्यों की अनदेखी करने में पूरी तरह से गलती की है, जिसका उद्देश्य पारित आदेश में विकृति है। यद्यपि विकृति का कोई विशिष्ट

संदर्भ नहीं है, लेकिन भौतिक तथ्यों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न का सामान्य उद्देश्य पूर्ण पुरस्कार में विकृति है। इसलिए, हम तथ्यों को देखने के लिए विवश हैं, न कि उनकी पुनः सराहना करने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि क्या प्रासंगिक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था और बाहरी विचारों को संगर्णित गया था, किस स्थिति में, आदेशों को स्पष्ट विकृति के आधार पर अलग करना होगा। यही कारण है कि हम मामले की शुरुआत से ही तथ्यों पर गौर करने का साहस करते हैं।

10. पहला तर्क यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जब्ती ज्ञापन से खुलासा किया जा रहा है, जो इस आधार पर है कि प्रतिवादी **ओम साई ट्रेडिंग कंपनी** (उपरोक्त) में निर्णय के आधार पर आग्रह करना चाहता है। उद्धृत मामले में, सुपारी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और धारा 111 के तहत, किसी भी आयात को जब्त किया जा सकता था। यहां तक कि जब ज़ब्ती एक अनिवार्य कार्रवाई थी, तब भी डिवीजन बेंच ने पाया कि एक *अनिवार्य शर्त* है, जो कि माल को ज़ब्त करने वाले अधिकारियों का यह मानना है कि इस तरह के सामान ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें, 'कटे हुए सूखे सुपारी (गहरे गुलाबी रंग के)' के रूप में वर्णित सामान को डीआरआई अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया था। कौन से माल निर्विवाद रूप से उस मामले में याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व में थे। यह जब्ती किसी भी क्षेत्र से नहीं की गई थी और इसे गोदाम या चेक पोस्ट के रूप में चिह्नित किया गया था और इसे बिहार राज्य के भीतर हाई-वे पर स्थापित टोल संग्रह बिंदु पर रोका गया था। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि माल की उत्पत्ति भारत के क्षेत्र, विशेष रूप से नेपाल के बाहर हुई थी। मालिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रेषक और प्रेषक के नाम का भी संकेत दिया गया था, जो भारत के क्षेत्र के भीतर थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रयोगशाला रिपोर्ट ने संकेत दिया कि सामान मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उक्त रिपोर्ट अधिनियम के तहत जब्ती के लिए एक वैध आधार नहीं थी।

11. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा, उद्धृत मामले में, विश्वास करने के कारण के गठन के कारणों के पूरक में उठाई गई दलीलों, में पाई गईं **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य** में निर्णय का उल्लंघन **(1978) 1 एससीसी 405** वजहें। यह विश्वास करने के लिए कि उद्धृत मामले में, आदेश में उपलब्ध नहीं थे और अदालत में जवाबी हलफनामे या संबोधित तर्कों के साथ पूरक नहीं किया जा सकता था। विश्वास करने का कारण केवल संदेह, गपशप या अफवाह नहीं माना गया था। ईमानदारी के आधार पर विश्वास उत्पन्न होना चाहिए और उचित आधार पर और यदि अधिकारी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कार्य करता है, तो यह क्षेत्राधिकार के साथ है जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है **शिव नाथ सिंह बनाम सी. आई. टी. (1972) 3 एस. सी. सी. 234** में। हमें ध्यान देना होगा कि **ओम साई ट्रेडिंग कंपनी** (ऊपर) में उक्ति थी उस मामले में सामने आने वाले विशेष तथ्यों पर, (i) माल के स्वामित्व के निर्विवाद होने पर, (ii) देश से बाहर से प्राप्त किए जाने वाले माल का कुछ भी संकेत नहीं देता है और (iii) प्रयोगशाला रिपोर्ट सीमा शुल्क अधिनियम के बाहर है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया में भेजे बिना ही जब्ती नोटिस को रद्द कर दिया गया। खंड पीठ ने यह भी देखा कि जब्त किए गए सुपारी की जानकारी, जो भारतीय मूल की नहीं है, कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों की राय है, जैसा कि पंचनामा में दर्ज है। न तो ऐसे अधिकारियों के विवरण का उल्लेख किया गया था और न ही यह केवल दृश्य निरीक्षण पर विदेशी मूल के सुपारी को खोजने में उनकी विशेषज्ञता के रूप में स्पष्ट था।

12. हमारी राय है कि जब्त किए गए माल की प्रकृति और इसे करने के तरीके को देखते हुए उक्त निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रोका गया व्यक्ति एक ट्रेन में सोना ले जा रहा था जो हावड़ा से शुरू हुई थी, जहां वह ट्रेन में सवार हुआ था और अपने गन्तब्य मुंबई तक पहुंचने से पहले उसे टाटानगर में रोका गया था। मुंबई में गंतव्य। माल के मालिक, जो इसमें प्रतिवादी है, को बाद में तलब किया गया था,

जिसने यह भी स्वीकार किया था कि माल किसी तीसरे पक्ष से खरीदा गया था और उसे उस व्यक्ति को सौंपा गया था जिसे रोका गया था; मालिक/प्रतिवादी का एक कर्मचारी। आभूषणों के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए इसे कोलकाता ले जाने के लिए भी सौंपा गया था। 13. इन स्पष्ट और सरल स्वीकृत तथ्यों के साथ, हम पहले माल के अवरोधन और पता लगाने पर विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन को देखते हैं, जो अपील ज्ञापन के पृष्ठ 73 पर है। मूल्यांकन एक सरकारी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया था और यह दोनों सोने की छड़ पर चिह्नों को इंगित करता है, जो इस प्रकार हैंः

"वाल्काम्बी सुइस (995) सी. एच. आई. निबंधक संस्थापक"

ये निशान दोनों सोने की छड़ में उपलब्ध हैं; जो प्रतिवादी के कर्मचारी के पास पर पाए जाते हैं, जिन्हें डी. आर. आई. अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है। सोने की छड़ें, उस पर पाठ के साथ, स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने कर्मचारी को सौंपी गई थी; व्यक्ति को रोका गया। डी. आर. आई. क्षेत्रीय इकाई पटना कार्यालय में तैयार किए गए 24.07.2017 का जब्ती ज्ञापन स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7,46 और 47 के उल्लंघन का संकेत देता है। धारा 7 सीमा शुल्क बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की नियुक्तियों की बात करती है। धारा 46 में पर माल की प्रविष्टि की आवश्यकता है। निर्धारित अनुसार घरेलू उपभोग या भंडारण के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके आयात और धारा 47 घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी की बात करती है। इसलिए, कथित उल्लंघनों पर विश्वास करने का कारण बहुत स्पष्ट है और वर्तमान मामले में, देश के बाहर से प्राप्त किए जा रहे सामान के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकती है, जो केवल एक दृश्य निरीक्षण से स्पष्ट है; स्विस निशान एक आम आदमी के लिए भी स्पष्ट थे जिनके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है। जाहिरा तौर पर केवल निरीक्षण से सोने की छड़ें भारत से प्राप्त नहीं की गई थीं।

14. अब, हम धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान पर आते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने विशेष रूप से आग्रह किया कि यह असंभव है कि जब्ती ज्ञापन और शपथ बयान एक ही व्यक्ति द्वारा देखे गए थे। हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि केवल एक अनहीनता का आरोप लगाया जा सकता है और असंभवता का नहीं। जब किसी व्यक्ति को अधिकारियों द्वारा गवाह के रूप में बुलाया जाता है और अधिकारियों के साथ जाने का निर्देश दिया जाता है, विशेष रूप से क्योंकि अवरोधन एक दूर की जगह पर था, तो नागरिक निश्चित रूप से सहमत होंगे; अधिक आधिकारिक प्रतिशोध के डर से। प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बयान को केवल असंभवता के आधार पर खारिज करने के बजाय, हमारी राय है कि बयान और उसके वापस लेने में देखा जाना चाहिए।

15. धारा 108 के तहत दिए गए बयान से ही रोके गए व्यक्ति की पहचान का पता चला, जिसे सहायक आयुक्त (निवारक) द्वारा प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, टिकरापारा धमतरी रोड, रायपुर के कार्यालय में दिनांकित 02.08.2017 के संचार द्वारा सत्यापित और सही पाया गया, जो पृष्ठ 76 पर अपील के ज्ञापन में जारी किए गए नोटिस के समर्थन में दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो अनुलग्नक-ए में प्रस्तुत किया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से जब्त किए गए सोने के मालिक की पहचान भी बयान से सामने आई है। बयान में यह भी स्वीकार किया गया कि वह व्यक्ति हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और वह रायपुर की यात्रा कर रहा था, इस दौरान सादे कपड़ों में कुछ लोगों ने उसे जगाया और खुद को डीआरआई, पटना के अधिकारियों के रूप में पेश किया। उन्होंने उसके शरीर की तलाशी ली और खोज के दौरान, पैंट के अंदर छिपाए और ढके हुए तस्करी किए गए सोने का पता चला। इतना बयान वापस नहीं लिया गया है।

16. जिस व्यक्ति को रोका गया था, उसने उस व्यक्ति के नाम का भी खुलासा किया था जिससे उसे कोलकाता में सोने की छड़ें मिली थीं, जिसने उसे प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया था। जो उसका नियोक्ता था। बयान से संकेत मिलता है कि रोके गए व्यक्ति ने अपनी जानकारी में स्वीकार किया है कि सोने की तस्करी बांग्लादेश से की गई थी, जैसा कि उसे एक सोनू ने बताया था, जिसने सोने की छड़ें अपने नियोक्ता, प्रतिवादी को सौंप दी थीं। बयान में सोनू और प्रतिवादी के मोबाइल नंबर का खुलासा किया गया है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास सोने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए, जिस व्यक्ति रोके गए से सोना जब्त किया गया था, उसने स्पष्ट रूप से सोने के कब्जे को स्वीकार किया था, जो स्पष्ट रूप से आयात किया गया था, उस पर निशान के अनुसार। भले ही हम बांग्लादेश से तस्करी की गई सोने की छड़ें प्राप्त करने के अपमानजनक बयान की अनदेखी करते हैं, जो बयान वापस ले लिया गया था, तथ्य यह है कि उन्होंने सुइस चिह्नों के साथ दो सोने की छड़ें रखने की बात स्वीकार की; जो निश्चित रूप से भारत के बाहर से प्राप्त की गई थीं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि सोने की छड़ें प्रत्यर्थी को आगे भेजने के लिए उसके कब्जे में थीं; जिसने बाद में इसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया था।

17. हम पहले ही देख चुके हैं कि यह मानने का कारण यह भी था कि यह दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज की कमी थी कि आयात अधिनियम की धारा 7,46 और 47 के अनुसार किया गया था। यह बहुत प्रासंगिक है कि यहां तक कि वापस लिए गए बयान में भी केवल यह कहा गया है कि दस्तावेजों और सामान के साथ आने वाले बिल वाउचर को जबरन उससे छीन लिया गया और डी. आर. आई. के अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिन्होंने अवरोधन किया। यह भी कहा गया था कि हमला किया गया था और अधिकारियों ने उसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।

18. हम देखते हैं कि वापस लेना, जो अनुलग्नक-आर/एफ में प्रस्तुत किया गया है, तब किया गया था जब रोका गया व्यक्ति न्यायिक हिरासत में था। वह अपने पहले के बयान से पीछे हटते हैं कि वह सोना कोलकाता से रायपुर ले जा रहे थे, जैसा कि सोनू ने उन्हें कोलकाता में सौंपा था। वापस लेने में, वह कहता है कि उसने अपने नियोक्ता द्वारा उसे सौंपी गई सोने की छड़ें लेकर रायपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी, और आभूषण बनाने के उद्देश्य से इसे कोलकाता ले गया था और चूंकि सुनार का पता नहीं चल सका था, इसलिए वह हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस से लौट रहा था। वापसी अवरोधन के समय सोने की छड़ें रखने की बात स्वीकार करती है। जिसका विवरण, जैसा कि डी. आर. आई. के साथ पाया जाता है, वह भी स्वीकार किया जाता है जिसे जब्त कर लिया गया था।

19. हम, वर्तमान में, यह मान लेंगे कि कहानी, जैसा कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति में कहा गया है, सही है। फिर भी यह स्थापित करना होगा कि सोना, जो एक दृश्य निरीक्षण पर भी, स्पष्ट रूप से देश के बाहर से प्राप्त होता है, अधिनियम के अनुसार आयात किया जाता है, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 46 और 47 के अनुसार इससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही हम उस व्यक्ति के बयान पर गौर करने में विफल रहें जिसे रोका गया था कि उसकी जानकारी में सोने की तस्करी बांग्लादेश से की गई थी। हम दोहराते हैं कि सोने की छड़ें रखने का तथ्य, जिसे डीआरआई अधिकारी ने उसके व्यक्ति से जब्त किया था और वह इसे हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस में ले जा रहा था, स्पष्ट रूप से स्थापित है। चाहे यह पहली बार रायपुर से लिया गया था या इसे कोलकाता में प्राप्त किया गया था, अप्रासंगिक तथ्य हैं; जब आयात के पहलू और जब्ती की वैधता को देखा जाता है, तो डी. आर. आई. अधिकारी द्वारा इस विश्वास के कारण कि सोने की छड़ें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयात नहीं की गई थीं।

20. उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों पर, हमने **गणपति ओवरसीज** (उपरोक्त) में निर्णय और विद्वान न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक **नरेश जे. सुखवानी** और **के. आई. पावन्नी** में गत से निकाले गए सिद्धांतों को देखा है (दोनों ऊपर)। हम विशेष रूप से **गणपति ओवरसीज** में (ऊपर) पैराग्राफ-53 से निकालते हैं:

> "**53**. इस प्रकार, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और संबंधित न्यायिक घोषणाओं के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि एक सीमा शुल्क अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति को तलब किया गया है और जो धारा 108 के तहत बयान देता है, वह आरोपी नहीं है। हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत संबंधित सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। धारा 108 का अंतर्निहित उद्देश्य उस व्यक्ति से सच्चाई का पता लगाना है जिसकी सीमा शुल्क उल्लंघन की घटना के संबंध में जांच की जा रही है। चूँकि इसका उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए सीमा शुल्क अधिकारी को इस प्रकार दर्ज किए गए बयान की सच्चाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि अभिलिखित कथन सही नहीं है, तो इस तरह के कथन को अभिलिखित करने की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। यह इस संदर्भ में है कि सीमा शुल्क अधिकारी, जिसे धारा 108 के तहत बयान दर्ज करने आदि का अधिकार दिया गया है, की यह सुनिश्चित करने की भारी जिम्मेदारी है कि बयान को निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है कि इस तरह से दर्ज किया गया बयान, जो साक्ष्य में स्वीकार्य है, बुनियादी न्यायिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के मानकों को पूरा कर सकता है। यह

स्वयंसिद्ध है कि जब कोई बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है, तो उसे न्यूनतम न्यायिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निश्चित रूप से, दबाव या जबरदस्ती के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह पता लगाना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का काम है कि क्या इस तरह के बयान की रिकॉर्डिंग में कोई दबाव या जबरदस्ती थी क्योंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।"

21. तत्काल मामले में उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि भले ही जबरदस्ती के आरोप को स्वीकार कर लिया गया हो, हमें विचार से बचना होगा, केवल उस व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को रोके किया गया कि, उसकी जानकारी में, सोना बांग्लादेश से तस्करी किया गया था, जैसा कि उसे उस व्यक्ति द्वारा बताया गया था जिसने उसे कोलकाता में पहुंचाया था। कोलकाता में डिलीवरी, जैसा कि इंटरसेप्ट किए गए व्यक्ति ने कहा है, को भी छोड़ना होगा। हमारे पास स्वामित्व, कब्जा और अवरोधन के साथ-साथ जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का विवरण भी है। इस तथ्य से कोई बच नहीं सकता है कि प्रतिबंधित पदार्थ का आयात किया गया था जैसा कि केवल एक दृश्य निरीक्षण से पता चला है, जो सोने की छड़ पर निशान का खुलासा करता है। अब, सवाल यह उठता है कि क्या सूचना प्राप्तकर्ता 2 के रूप में संदर्भित माल के कथित मालिक, प्रतिवादी ने अपने द्वारा किए गए कानूनी आयात के माध्यम से वैध कब्जा प्राप्त किया था।

22. इस मोड़ पर, हम मूल और अपीलीय आदेशों को देखते हैं जिन्हें प्रतिवादी बनाए रखना चाहता है। न्यायाधिकरण का आदेश प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के तर्क को निकालता है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तर्क और आगे के निष्कर्षों को इसमें अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल के रूप में चुनौती दी जाती है। विभाग ने इस तथ्य पर भरोसा जताया कि सूचना प्राप्तकर्ता

संख्या 3 और 4, पुत्र और पिता, डी. टी. के स्वामित्व और उपयोग में आने वाली कारों में से कोई भी नहीं है। जिसने कथित तौर पर सूचना प्राप्तकर्ता सं. 2 को सोने की छड़ें बेचीं, वह भिलाई से रायपुर गया था। यह सूचना संख्या 3 द्वारा दिए गए विशिष्ट कथन के संदर्भ में है; भिलाई में स्थित एक व्यापारी, कि उसने सूचना प्राप्तकर्ता सं. 2 को माल पहुँचाया था; जिनका व्यवसाय रॉची में था। जांच से पता चला कि डी. आर. आई. को दिए गए सूचना प्राप्तकर्ता सं. 3 और 4 के स्वामित्व वाली कारों में से कोई भी खारून टोल प्लाजा को पार नहीं कर पाई। सुनार 'सुभ', जिसे कथित तौर पर सोने की छड़ें गहने में बदलने के लिए भेजी गई थीं, जिसका मोबाइल नंबर प्रतिवादी द्वारा प्रकट किया गया था और जिस व्यक्ति पर मालिक से करीगर का परिचय कराने का आरोप है, मुकेश गणात्रा, दोनों ने मालिक के तर्क का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। मुकेश गणात्रा ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि हालांकि वह प्रतिवादी, सूचना प्राप्तकर्ता सं. 2 से परिचित थे, लेकिन उन्होंने प्रतिवादी से किसी भी कारीगर का परिचय नहीं कराया था। जिस व्यक्ति के पास कथित रूप से सुभ का मोबाइल नंबर था, उसने भी प्रतिवादी के मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। किस परिस्थिति में, मूल प्राधिकारी ने पाया कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 123 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा।

23. प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि विभाग का पूरा मामला रोके गए व्यक्ति के इकबालिया बयान के इर्द-गिर्द घूमता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि धारा 108 के तहत दर्ज किए गए बयान को विशेष रूप से दबाव में बताया गया था और मूल प्राधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उन्होंने बयान को वापस नहीं लिया था, जबकि वास्तव में, बयान को विशेष रूप से वापस ले लिया गया था। यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 108, हालांकि ठोस साक्ष्य है, इस पर कार्रवाई करने से पहले कुछ पुष्टि उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी भी पुष्टि हो सकती है। यह पाए जाने पर कि रोके गए व्यक्ति ने अपना बयान वापस ले लिया है और कोई पुष्टि नहीं होने के कारण, इसे

किसी भी तरह से निर्भर होने में असमर्थ माना गया। रिलायंस को उस व्यक्ति के वापस लिए गए बयान पर भी भरोसा रखा गया था जिसे रोका गया था कि वह वास्तव में वैध दस्तावेज ले जा रहा था, जिसे डी. आर. आई. अधिकारी ने नष्ट कर दिया था, जिसने उसे रोका और बाद में गिरफ्तार कर लिया। वापस लिए गए बयान का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं पाया गया

24. यह पाया गया कि मेसर्स सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सूचना प्राप्तकर्ता सं. 4 के स्वामित्व वाली एक डीलरशिप ने उक्त सोने की छड़ की आपूर्ति को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए प्रासंगिक बिल और स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया था और विक्रेता द्वारा प्राप्त पूरे भुगतान की पुष्टि भी की थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विभाग ने उक्त सोने की छड़ों के स्रोत का खुलासा करने के लिए विक्रेता के दरवाजे से आगे नहीं बढ़ा, ताकि को हटाने या गलत साबित किया जा सके। किसी अन्य व्यापारी से सोने की छड़ें खरीदने के बारे में मालिक का दावा को हटाने या गलत साबित किया जा सके। उक्त लेन-देन की प्रामाणिकता और वास्तविकता पर केवल इस अनुमान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि विदेशी निशान वाली उक्त सोने की छड़ें भारत में तस्करी करके लाई गई थीं, विशेष रूप से जब धारा 108 के तहत बयान वापस ले लिया गया था और किसी भी भौतिक साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा सोनू और चंदन मलिक के ठिकाने का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिनमें से पूर्व को वापस लिए गए बयान में तस्करी का सामान सौंपने वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोने की कथित तस्करी की पूरी श्रृंखला का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। बिक्री और खरीद का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए गए चालान में सोने की छडों के विवरण की अनुपस्थिति को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के निरस्त होने के बाद, उदार अर्थव्यवस्था में अप्रासंगिक माना गया था; जो एक

कानूनी आवश्यकता नहीं है। न्यायाधिकरण ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया।

25. हम पहले ही इस स्वीकृत स्थिति का उल्लेख कर चुके हैं कि बरामद की गई दो सोने की छड़ें विदेश से प्राप्त की गई थीं; जो निर्विवाद है। रोके गए व्यक्ति के कब्जे को भी स्वीकार किया जाता है और कहा जाता है कि वर्तमान अपील में स्वामित्व प्रतिवादी पर है। अधिनियम की धारा 123 (2) यह विशेष रूप से सोने पर लागू होता है और जब इस अधिनियम के तहत सोना जब्त किया जाता है, तो उप-धारा (1) के अनुसार इस उचित विश्वास पर कि इसकी तस्करी की गई है, सबूत का भार पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिससे जब्ती की गई थी या ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करता है जो मालिक होने का दावा करता है।

26. हमने पाया है कि सोने की छड़ का विवरण ही इंगित करता है कि यह आयातित है। जांच की कवायद पर आगे की जांच हालांकि महत्वहीन है, क्योंकि इसमें अपीलीय अधिकारियों द्वारा गलती की गई है, इसलिए हमने जांच को आगे बढ़ाने के तरीके को देखा। धारा 108 के तहत बयान से पता चला कि कोलकाता के एक सोनू ने सोना उस व्यक्ति को सौंप दिया था जिसे रोका गया था, जिसने यह भी जानकारी दी थी कि इसे बांग्लादेश से देश में तस्करी करके लाया गया था। दो मोबाइल नंबर सोनू के होने का संकेत दिया गया था, जो उपभोक्ता आवेदन पत्र (सीएएफ) की खरीद पर श्री चंदन मलिक और श्री सचिन गुप्ता से संबंधित पाए गए थे। उन्हें समन जारी किए गए और दोनों ने जब्ती के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया, एक सीधे उनसे और दूसरा एक वकील के माध्यम से। हम इन तथ्यों पर ध्यान देते हैं, केवल पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही पाया है कि धारा 108 के तहत कोलकाता से सोने की प्राप्ति के विवरण को छोड़ा जा सकता है हलॉकि जिस

प्राधिकारी ने माल को जब्त किया है, उसे मामले में सामने आए तथ्यों की जांच नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

27. फिर हम सोहन वर्मा @सुभ करिगर के खिलाफ उठाए गए 'करिगर मुद्दे की पर्ची' पर आते हैं, जो अपील के ज्ञापन के पृष्ठ 79 पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ उपलब्ध है। उक्त दिनांकित 22.07.2017 दस्तावेज़ में कारीगर का नाम 'सुभ' के रूप में दिखाया गया है। समन कारीगर को जारी किया गया था, लेकिन उसे "प्राप्तकर्ता स्थानांतरित" के समर्थन के साथ बिना भेजे वापस कर दिया गया था। पुनः समन जारी किया गया और एक अधिवक्ता से जवाब प्राप्त हुआ कि श्री सोहन वर्मा इसमें प्रतिवादी को नहीं जानते थे। प्रत्यर्थी के बयान के अनुसार; एक श्री मुकेश गणात्रा ने उसे सोहन वर्मा से मिलवाया, जिसका मोबाइल नंबर भी प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया था। 15.12.2017 को दर्ज सोहन वर्मा और मुकेश गणत्र के स्वैच्छिक बयानों ने प्रतिवादी द्वारा स्थापित इस कहानी को स्पष्ट रूप से ध्वस्त कर दिया कि उसने एक कारीगर पर्ची जारी की थी और आभूषण बनाने के उद्देश्य से रोके गए व्यक्ति के माध्यम से सोने की छड़ें भेज दी थीं। सोहन वर्मा ने विशेष रूप से कहा कि वह मुकेश गणात्रा या प्रतिवादी या जिस व्यक्ति को रोका गया था, उसे नहीं जानते हैं और जिस व्यक्ति को रोका गया था, उसने उन्हें कभी टेलीफोन पर फोन नहीं किया। मुकेश गणात्रा जो सोने के आभूषणों का व्यवसाय भी कर रहे थे, सुभ करिगर @सोहन वर्मा के बारे में अज्ञानता का नाटक किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उस प्रतिवादी को जानते थे जिसके साथ उनके कोई व्यावसायिक संबंध नहीं थे और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने शुभ करिगर के नाम से किसी व्यक्ति को प्रतिवादी से मिलवाया था।

28. हमने सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2 से 4 के बयानों को भी देखा है, जैसा कि अनुलग्नक-ए में निकाला गया है। सूचना संख्या 2, इसमें प्रतिवादी को तीन बार तलब किया

गया था और बयान 04.08.2017,05.08.2017 और 18.08.2017 को दर्ज किए गए थे। सबसे पहले, प्रतिवादी ने जनवरी तक स्टॉक विवरण और बिक्री और खरीद चालान के साथ-साथ 58,80,000/- मूल्य की 2 किलोग्राम सोने की बार की खरीद के लिए सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड से जारी किए गए 21.07.2017 के बिल की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। उन्होंने कारीगर इश्यू पर्ची की मूल प्रति भी प्रस्तुत की, जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त और हस्ताक्षर किए गए थे और शुभ को संबोधित श्री आदिनाथ ज्वेलर्स के लेटर-हेड में पत्र सं. .2702/2017 की एक फीकी प्रति भी प्रस्तुत की। करीगर पर्ची और शुभ को संबोधित पत्र दोनों का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि पहले से ही यह पाया गया है कि शुभ का अस्तित्व उस तरह से नहीं था जिस तरह से उन्हें एक करीगर के रूप में चित्रित किया गया था।

29. सोने की छड़ें रोकने और जब्त करने से पहले प्रस्तुत चालान 21.07.2017 का था, लेकिन अवरोधन से पहले किसी भी समय खरीदे गए सोने के लिए किसी भी राशि के भुगतान का संकेत देने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरदाताओं द्वारा सहेली रत्न और आभूषण विक्रेताओं को आर. टी. जी. एस. के माध्यम से 02.08.2017 को 5,50.000/- भुगतान की गई थी। 18.08.2017 को जब उन्होंने एक बयान दिया था, तो प्रत्यर्थी ने कहा था कि चालान की मूल प्रति उनके पास थी और उन्होंने गलती से इसे नहीं लाया था। यदि चालान की मूल प्रति उसके पास थी, तो हमें आश्चर्य होता है कि वह कौन सा दस्तावेज था जो माल के साथ था जैसा कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 द्वारा कहा गया है। यहाँ, हमें यह देखना होगा कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 के वापस लिए गए बयान में ऐसा कोई मामला नहीं था कि मूल चालान उसके पास था। अस्पष्ट बयान यह था कि ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिन्होंने उन्हें रोक लिया था। यहां तक कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2 भी यह नहीं कहता है कि उसने मूल चालान सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 को दिया था, जो सोना कोलकाता ले जा रहा था और रांची वापस जा रहा था, जैसा कि सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 और 2 द्वारा स्थापित किया गया था।

30. सूचना प्राप्तकर्ता सं. 3 सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक था और सूचना प्राप्तकर्ता सं. 4 भी, जो सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स के संस्थापक और सूचना प्राप्तकर्ता सं. 3 के पिता थे। उनके अनुसार, जब्त किए गए सोने का भुगतान रुपये की किश्तों में किया गया था। 5,50,000 रु. 02.08.2017 को 32,00,000 रु. -28.08.2017 को और 11,00,000/-रु. 31.08.2017 को डी. आर. आई. द्वारा सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2, मालिक/प्रतिवादी के तीन बयान दर्ज किए जाने के बाद ऐसी अंतिम दो किश्तें की गई हैं। सूचना प्राप्तकर्ता सं. 3 ने बयान दिया कि उसने अपने पिता के साथ श्री आदिनाथ ज्वेलर्स के दुकान परिसर में 21.07.2017 को सामान पहुंचाया था। उन्होंने बिल बुक के दो सेट तैयार किए जिनमें से एक में से 5 बिल 01.05.2017 से 10.05.2017 के बीच जारी किए गए थे। सीरियल No.1-6 से बिल बुक 01.04.2017 से 10.09.2017 के बीच सोने की बिक्री से संबंधित है और सीरियल No.1-9 से बिल बुक 05.04.2017 से 20.08.2017 तक सर्राफा बिक्री से संबंधित है। इसलिए, बिक्री क्रमिक रूप से नहीं की गई थी और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसके द्वारा आदिनाथ ज्वैलर्स को 2 किलोग्राम सोने के 21.07.2017 के पर जारी किए गए बिक्री चालान की वास्तविकता स्थापित की जा सके, जैसा कि उसमें दिखाई गई तारीख को जारी किया गया था। सूचना प्राप्तकर्ता सं..3 और 4 दोनों ने डी. आर. आई. के अधिकारियों को सूचित किया कि वे सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2 से अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, लेकिन जोर देकर कहा कि उन्होंने 2 किलोग्राम सोना उधार दिया था; अत्यधिक संदिग्ध है।

31. प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि जब्त किए गए सोने की छड़ें सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थीं, सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए दिनांक 1 के चालान पर पूरी तरह से भरोसा किया था। हम यह मान कर नहीं रह सकते हैं कि रखी गई निर्भरता पूरी तरह से अप्रासंगिक है क्योंकि किए गए बिल बुक के दो सेट में सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स

और आदिनाथ ज्वैलर्स के बीच लेनदेन को स्थापित करने के लिए और सबूत की आवश्यकता होती है, जिस दिन ऐसा हुआ था; अवरोधन और जब्ती से पहले, विशेष रूप से जब से खरीद के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। इस संदर्भ में देखा जाए तो यह उचित है कि चालान में बेचे गए सोने की छड़ का विवरण नहीं है, इस प्रकार, बेचे गए सोने की पहचान करना असंभव हो जाता है, क्योंकि यह वही सोना है जो सूचना प्राप्तकर्ता सं. 1 के व्यक्ति से बरामद किया गया था। फिर, अगर सोना बरामद किया जाता है, तो उसके भौतिक रूप से उसके स्रोत का खुलासा नहीं होता है; शायद चालान में साक्ष्य मूल्य की झलक होती, भले ही भुगतान सोने की जब्ती के बाद किया गया हो; जो चालान के साक्ष्य मूल्य और लेनदेन की वास्तविकता को कम करता है।

32. जैसा कि वर्तमान स्थिति है, चालान भले ही सहेली रत्न और आभूषण विक्रेताओं और आदिनाथ आभूषण विक्रेताओं के बीच लेनदेन को स्थापित करता है, यह सबूत के बोझ का निर्वहन नहीं करता है क्योंकि आयात सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार किया गया है। यदि सहेली जेम्स एंड ज्वैलर्स ने इसे दाखिल किए गए प्रवेश के उचित बिल द्वारा आयात किया था और इसे घर के उपभोग के उद्देश्य से एक अधिसूचित प्रवेश बिंदु से प्राप्त किया था, तो और केवल तभी प्रमाण का भार धारा 123 के तहत छूट दी जाए और सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 1 से जब्त किए गए सामान को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही से छूट दी जाए। सोने की छड़ के मालिक द्वारा पेश की गई कहानी का झूठ, एक अन्य परिस्थिति है जो मालिक द्वारा उठाए गए दावे के खिलाफ और ज़ब्ती की कार्यवाही के पक्ष में है।

33. हमारे द्वारा बताए गए कई कारणों से 21.07.2017 दिनांकित चालान को वास्तविक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि सोने की छड़ें सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 2 की थीं और उन्होंने इसे सूचना प्राप्तकर्ता संख्या 3 और 4 से खरीदा था; जैसा कि

कहानी में बताया गया है, तो इसे बिना किसी सावधानी के खरीदा गया था। उस परिस्थिति में जब सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोने की पट्टियां जब्त की जाती हैं और जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह खरीदार; आदिनाथ ज्वैलर्स, या विक्रेता; सहेली रत्न और आभूषण विक्रेता को, यह साबित करने के लिए है कि सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोना वैध रूप से विदेश से देश में आयात किया गया था। देश के बाहर निर्मित सोने का मालिक कोई भी हो, यदि इसे उसी रूप में जब्त किया जाता है, तो उक्त सोने को जारी करने का दावा करने वाले मालिक को प्राधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि इसे सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत भारत में लाया गया था। यह मालिक या मालिक पर रखी गई कठोरता है। धारा 123 द्वारा माल, जो सबूत का भार पूरी तरह से उस व्यक्ति पर डालता है जिसके कब्जे से या उस मालिक पर, जिसने उक्त सोना उस व्यक्ति को सौंपा है जिसके पास यह है, उस स्रोत को स्थापित करने के लिए जिससे इसे प्राप्त किया गया है।

34. अपीलीय अधिकारियों ने लेनदेन के प्रमाण के अभाव के संबंध में मूल प्राधिकरण के निष्कर्षों को पाया है, जिसमें माल की आवाजाही भी शामिल है, जो केवल प्रस्तुत किए गए चालान के कारण खराब है। हमने पाया है कि चालान कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिस पर कोई निर्भरता रखी जा सके। भले ही इस तरह की निर्भरता रखी जा सकती है, वर्तमान मामले में, सोने की छड़ें; जो स्पष्ट रूप से देश के बाहर से निर्मित और प्राप्त की गई थीं, यह साबित किया जाना चाहिए कि सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देश में लाई गई थीं। हम राजस्व-अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ, जब्त किए गए माल के मालिक, विशेष रूप से न्यायाधिकरण और प्रथम अपील प्राधिकरण के तर्क को अप्रासंगिक सामग्री और बाहरी विचारों पर आधारित पाते हुए, विवादित आदेशों को विकृत बनाते हुए, कानून के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

35. हम अपीलीय प्राधिकरणों के आदेशों को दरकिनार करते हैं और मूल प्राधिकरण के आदेशों को बहाल करते हैं। हम 5,000/- रुपये की गणना की गई लागत के साथ अपील की अनुमति देते हैं। जो राजस्व द्वारा प्रत्यर्थी से वसूली की जाए।

36. आई.ए., यदि कोई हों, तो उन्हें भी बंद किया जा सकता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

हरीश कुमार, न्यायमूर्ति

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

सुजीत/शारुन

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।